अध्याय 19
सूचना प्रौद्योगिकी पहलें/ई-गर्वनेन्स

19.1 मंत्रालय में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उन्नत दक्षता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ई-गर्वनेन्स कार्यान्वित कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। स्कीम के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान की गई हैः-

- मंत्रालय में लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) कनेक्टिविटी का विस्तार /उन्नयन।
- मंत्रालय तथा जैसलमेर हाउस के सभी अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण ।
- पूरे देश में डी जी एल डब्ल्यू कार्यालय से अपने 9 केन्द्रीय कार्यालयों में कनेक्टिविटी ।
- डाक के तेजी से डिलीवरी और कारगर प्रबोधन हेतु प्रत्येक स्तर पर केन्द्रीय रजिस्ट्री में उच्च क्षमता वाली स्केनर सुविधा मुहैया कराना।
- सभी पुराने कम्प्यूटरों के स्थान पर अद्यतन प्रौद्योगिकी वाले नए कम्प्यूटरों को प्रतिस्थापित करना और टी एफ टी मॉनीटर का प्रावधान करना ।
- वी.डी.ओ. कान्फेंसिंग प्रणाली को शुरू करना ।
- नेटवर्क को चलाने और प्रबंधन करने तथा डाटावेस को सृजित करने और प्रबंधित करने हेतु सॉफ्टवेयर की खरीद ।
- प्रयोक्ताओं के तकनीकी कौशलों को उन्नत बनाना ।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों और प्रशासन तथा महत्वपूर्ण अनुभागों को मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर मुहैया कराना ।
- जहां कहीं अपेक्षित हो संबद्ध साफ्टवेयर मुहैया कराना।
- प्राथमिकता के आधार पर सॉफ्टवेयर की खरीद करना/विकसित करना।

19.2 इस स्कीम के लिए दसवीं योजना में 800 लाख रुपये के परिव्यय की आशा है। यह आबंटन सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन पर व्यय के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय की निधि के 2 से 3 प्रतिशत के भीतर ही सीमित रहेगी ।

19.3 यह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु योजना निधियों के 2-3 प्रतिशत के प्रावधान हेतु योजना आयोग के निदेशों पर बनाई गई एक सतत

चलने वाली योजना है। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में कम्प्यूटरीकरण का सुधार करने और उनकी दक्षता में सुधार लाने के लिए अभियान शुरू करना है। दसवीं योजना में, क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालय के साथ उनके कार्य-चालन/क्रियाकलापों को एकीकृत करने हेतु सूचना प्रोद्योगिकी पहलें की जाएंगी।

19.4 इस योजना की प्रगति का प्रबोधन इस प्रयोजन हेतु बनाई गई सूचना प्रौद्योगिकी समिति द्वारा नियमित रूप में किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन हेतु योजना स्कीम योजना बनाने निष्पादन करने, और समीक्षा करने में सहायता करने तथा प्रबंधन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक होता है। परियोजना समीक्षा उप-समिति मंत्रालय में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक रूप में समीक्षा करेगी, संसाधनों के आबंटन की निगरानी करेगी, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी और उपचारात्मक/वैकल्पिक कार्रवाई योजना के बारे में सलाह देगी ताकि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मॉडय़ू का लक्ष्य के अनुसार विकास और कार्यान्वयन किया जा सके । यह भी सुनिश्चित करती है कि मानकों और विकास टूलों की एकरूपता का उपयोग मंत्रालय में अनुप्रयोजन मॉडल्यू के विकास में किया जा सके ।

19.5 ई-गर्वनेन्स के क्षेत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय की कुछ नवीन पहलें निम्नानुसार हैः-

वर्ष 2006-2006 दिसम्बर 2006 तक के दौरान वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां ः

लैंन कनेक्टिविटी :- मंत्रालय और जेसलमेर हाउस में लगभग सभी कम्प्यूटरों में लैन विस्तारित किया गया है। इंटरनेट के लिए लीज्ड लाइन कनैक्शन इंटरनेट तक समस्या मुक्त पहुंच मुहैया कराने हेतु उपलब्ध हैं ।

वेबसाइटः- एन आई सी की सहायता से मंत्रालय के वेबसाइट में सुधार लाने के प्रयास जारी हैं ताकि इसे अत्यधिक गतिशील और सक्रिय बनाए जा सके। जनता से सींधे शिकायते और फिडबैक प्राप्त करने के लिए पहले से ही अलग से एक विन्डो खोला गया है ।

पी ओ ई कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण (अब भारतीय विदेश कार्य के अंतर्गत)ः:- दिल्ली और बाहर के उत्प्रवास महासंरक्षी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण ।

औद्योगिक प्रभाग का कम्प्यूटरीकरण :- आई आर प्रभाग का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया गया था । इस पैकेज का आशय औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में मंत्रालय के कार्याचालन के बारे में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था करना है।

इम्पलाइवेयर सॉफ्टवेयरः- प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए, मंत्रालय के इंटरनेट पर जी.पी.एफ.खातों सहित सभी सेवा दस्तावेजों को रखने हेतु "इम्पलाइवेयर" साफ्टवेयर पैकेज लागू है यह साफ्टवेयर इस सूचना को मंत्रालय के सभी अधिकारियों और स्टाफ को सीधे उपलब्ध कराएगा ।

प्रशिक्षण :- क्षमता निर्माण के उद्देश्य से स्टॉफ के साथ-साथ अधिकारियों को एन आई सी की सहायता से नियमित रूप से समुचित कम्प्यूटर कौशल प्रदान किया जाता है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीदः- सरकारी कार्य के सूचारू रूप से और तेजी से निपटान हेतु जब भी अपेक्षित होता है अधिकारियों के कार्यालयों /अनुभागों में उपयोग हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद की जा रही है।

****